

कॉर्ड-11014/7/2019-समन्वय
भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
(समन्वय प्रभाग)

तृतीय तल, कौशल भवन,
न्यू मोती बाग, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 22.11.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एसडीई मंत्रालय से संबंधित मंत्रीमंडल के लिए मासिक सार- के संबंध में।

मुझे सितम्बर, 2024 के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का मासिक सार सूचनार्थ अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संलग्नक: यथोक्त



(अखिलेश कुमार राय)
भारत सरकार के अवर सचिव

प्रति:

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

मंत्रीमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110001

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की सितंबर, 2024 माह की संक्षिप्त रिपोर्ट इस प्रकार है:

लंबे समय से चल रहे अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण लंबित नीतिगत और अन्य मामले

कुशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (एसआईआईसी)

वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 कुशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में, वाराणसी और भुवनेश्वर में ऐसे दो केंद्र कार्यरत हैं और चालू वित्त-वर्ष के दौरान ऐसे आठ और केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इन केंद्रों के संचालन और इष्टतम उपयोग में विदेश मंत्रालय के साथ मुद्दों को हल करने के लिए, और कैबिनेट सचिव द्वारा अनुमोदित, एक मसौदा सीओएस नोट विदेश मंत्रालय को परिचालित किया गया था। इस महीने के दौरान विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों का इंतजार किया गया।

कैबिनेट सचिवालय या प्रधानमंत्री कार्यालय में लंबे समय से लंबित प्रस्ताव/संदर्भ

कुशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी)

एमएसडीई की प्रमुख स्कीमों, अर्थात् प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), पीएम-राष्ट्रीय शिक्षता संवर्धन स्कीम (पीएम-एनएपीएस) और जन शिक्षण संस्थानों को सहायता स्कीम (जेएसएस) पर 27 जुलाई, 2022 को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में विचार किया गया। ईएफसी ने तीनों स्कीमों को एक समग्र केंद्रीय क्षेत्र स्कीम "कुशल भारत कार्यक्रम" के अंतर्गत 8,800 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ संयोजित करने की सिफारिश की। तदनुसार, ईएफसी की सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट की मंजूरी के लिए एक मसौदा नोट प्रस्तुत किया गया था। कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, जिसके लंबित रहने तक व्यय विभाग द्वारा कोई रिलीज नहीं की गई है।

ऐसे किसी भी मामले का विवरण जिसमें व्यवसाय के नियमों से विचलन हुआ हो।

हमारी समझ से ऐसा कोई नहीं है।

अन्य मामले/महत्वपूर्ण घटनाक्रम

समझौते/भागीदारी

- भारत और सिंगापुर के बीच शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास पर समझौता ज्ञापन (एमओयू), जिस पर 4-5 सितंबर 2024 के दौरान माननीय प्रधान मंत्री की सिंगापुर यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, दोनों देशों के बीच टीवीईटी और कौशल विकास में सहयोग और क्षमता-विकास के नए रास्ते खोलेगा।
- एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ भागीदारी। विभिन्न विमानन और गैर-विमानन जाँब रोलों में नियोजन के साथ सह-भुगतान मॉडल के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

- दिल्ली और कर्नाटक में लॉजिस्टिक्स से संबंधित जॉब रोलों के लिए कैप्टिव प्लेसमेंट कार्यक्रम प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट सप्लाय चैन ऑपरेशन अकादमी के साथ भागीदारी।
- 8,000 प्रशिक्षकों का एक पूल विकसित करने के लिए, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, आईसीएटी अकादमी और राष्ट्रीय निर्माण अकादमी से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) लिया गया है।
- गिग श्रमिकों को कौशल प्रदान करने के लिए, हमने 'स्विगी कौशल पहल' शुरू की है, जो खाद्य वितरण, त्वरित वाणिज्य नेटवर्क तथा रेस्तरां संचालन में कौशल और रोजगार के अवसरों की एक श्रृंखला प्रदान करती है।

एमएसडीई भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ उनकी संबंधित स्कीमों के कौशल घटकों के वितरण के लिए सहयोग कर रहा है।

- हमने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के सहयोग से 19 राज्यों के 27 जिलों में पायलट आधार पर 3,850 किशोरियों और महिलाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें गैर-पारंपरिक क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, ताकि उनकी कार्यबल भागीदारी, सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन को बढ़ाया जा सके।
- एमएसएमई के साथ: माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 20 सितंबर को वर्धा में पीएम विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना के तहत, एमएसडीई ने सितंबर 2024 तक 30 राज्यों के 531 जिलों में 2,872 प्रशिक्षण केंद्रों में 9.64 लाख विश्वकर्माओं को कौशल प्रदान किया है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ, एमएसडीई ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अलावा, पीएम सूर्य घर योजना (रूफ टॉप सोलर पीवी स्थापना और रखरखाव के लिए) के तहत भी कौशल विकास का काम शुरू किया है, जिसके तहत महीने के दौरान 448 उद्यमियों के साथ लगभग 30,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ: पीएम-जनमन स्कीम के अंतर्गत, 1,000 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की क्षमता-निर्माण (महीने में 23,00 उम्मीदवारों और 500 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण), और पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (30 चिन्हित जनजातीय जिलों में 30 नए कौशल केंद्रों की स्थापना)।
- गृह मंत्रालय के साथ: वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत कौशल।
- संस्कृति मंत्रालय: पांडुलिपियों के संरक्षण में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ कौशल।
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग; उचित मूल्य की दुकान के मालिकों का कौशल विकास।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)

- आईटीआई भारतीयों के दीर्घकालिक कौशल विकास की रीढ़ बने हुए हैं। इस महीने के दौरान, 17,43,341 आईटीआई छात्रों की अखिल भारतीय व्यापार

परीक्षा (एआईटीटी) (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) 9 सितंबर, 2024 को बिना किसी शिकायत के सफलतापूर्वक पूरी हुई और परिणाम 15 सितंबर, 2024 को घोषित किया गया। 87% प्रशिक्षुओं ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

- चालू महीने के दौरान, एमएसडीई ने उद्योग और राज्यों के साथ केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित नई आईटीआई उन्नयन योजना को डिजाइन करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया आयोजित की, एमएसडीई, विश्व बैंक और एडीबी के सदस्यों वाली टीमों ने केंद्रित परामर्श के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा, झारखंड और ओडिशा राज्यों का दौरा किया।
- सितंबर 2024 से शुरू होने वाले आईटीआई के नए शैक्षणिक सत्र (2024-25) के लिए, नए युग के पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जैसे सेमीकंडक्टर तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, 5 जी नेटवर्क तकनीशियन और साइबर सुरक्षा सहायक।

कौशल ऋण स्कीम

जैसा कि बजट में घोषणा की गई थी, नए मॉडल कौशल ऋण स्कीम को अधिसूचित किया गया और स्कीम के बारे में जागरूकता पैदा करने और सफल कार्यान्वयन के लिए 26 सितंबर 2024 को भारतीय बैंक संघ, एनबीएफसी/एनबीएफसी-एमएफआई/एसएफबी के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई।

विश्व कौशल प्रतियोगिता

10-15 सितंबर, 2024 तक फ्रांस के लियोन्स में आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता में, भारत ने 52 कौशल में भाग लिया और 4 कांस्य पदक और 12 पदक के साथ 13वां स्थान हासिल किया।

स्वच्छता ही सेवा

एमएसडीई ने अपने संबद्ध और स्वायत्त निकायों के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान 4.0 चलाया। कुल मिलाकर, एमएसडीई ने 2,831 कार्यक्रमों की पहचान की और एसएचएस 2024 के लिए "स्वच्छता में जन भागीदारी" थीम के तहत 2,24,231 स्व-सेवकों के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। इसके अलावा, "एक पेड़ माँ के नाम" कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में 11,778 पौधे लगाए गए।

उपर्युक्त पहलों के अलावा, सभी डिलिवरेबल्स के शीघ्र निपटान में अत्यधिक तत्परता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई आंतरिक उपायों के माध्यम से कार्य निष्पादन को युक्तिसंगत बनाने की चल रही प्रक्रिया जारी रही।
